[श्री हरीश कुमार गंगवार]

मैं माननीय विदेश मंत्री से आग्रह-पूर्वक अनुरोध करता हूं कि वह पास-पोर्ट बनवाने की इच्छुक जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए बरेली व गोरखपुर में भी पासपोर्ट बनाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की कृपा करें ।

(ii) NEED FOR A NEW HIGHWAY LINK BETWEEN AHMEDABAD AND VADODARA.

SHRI R. P. GAEKWAD (Baroda): The Gujarat State Government has formulated a proposal to link Ahmedabad and Vadodara by a new highway. This road would be for automobiles only and no other modes of transport would be permitted to enter. The feasibility report prepared by the Gujarat Government reavels that this would result in enormous saving of fuel. The new highway will reduce the motorable distance between the two cities by only 14 kms. from 92 kms. It will result in saving one-sixth of the fuel now consumed. It will increase speed of the vehicles and save time. The State Government will earn a revenue of 17.33 crores by way of toll tax. The estimated investment on the project is 70.6 crores. It will yield an annual return of 14.5 per cent on investment. And in the long run it will stimulate the redesigning of road systems. In view of increase in the number of automobiles and consequent pressure on our roads, the project has tremendous economic potentialities. I request the Union Government and specially the Ministry of Transport and Shipping to take initiative in the matter and help Gujarat in launching the project.

(iii) NEED FOR GIVING FINANICAL ASSISTANCE TO U.P. GOVERNMENT FOR PAYMENT OF SUGARCANE ARREARS TO FARMERS.

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : मान्यवर, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के जिम्मे गन्ना किसानों का लगभग 70 करोड़ रुपये से अधिक बकाया पड़ा हुआ है, साथ ही जितनी चीनी मिलें हैं उनके गोदाम चीनी से भरे पड़े हैं । गन्ने के पिराई का सत्र शुरू होने वाला है । मिलों की हालत आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त ही दयनीय हो चुकी है । बैंक की साख समाप्त हो चुकी है । अगला सत्र शुरू करने के लिये मिलों के पास अपनी मशीनरी रिपेरिंग करने के लिए भी रुपये नहीं हैं । इस समय उत्तर प्रदेश सूखे और बाढ़ से तबाह हो चुका है । लाखों किसान परिवारों के मन में इस बात की आशंका हो गई है कि अगले सत्र में हमारे गन्ने की पिराई मिलों द्वारा हो पायेगी या नहीं, साथ ही इतनी बड़ी रकम मिलों के जिम्मे बकाया पड़ी हुई है । अगले सत्र का भुगतान मिल कर पायेगा या नहीं यह स्थिति अत्यन्त ही भयावह है ।

हमें ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार से विशेष परिस्थिति में आर्थिक सहायता की याचना की है । किन्तु आज तक कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल सका । ऐसी दशा में मैं माननीय कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पुराने गन्ने की कीमत अगले सत्र में जो चीनी मिलों द्वारा तैयार होगी, उसके रखने की व्यवस्था तथा अगले सत्र में गन्ने के मूल्य का भुगतान करने के लिए क्या प्रबंध किये जा रहे हैं ? बिहार प्रदेश में भी गन्ना किसानों और चीनी मिलों की ऐसी ही हालत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मनीराम बागड़ी ।

श्री मनी राम बागड़ी : (हिसार) : डिप्टी स्पीकर साहब अखबार में रिपोर्टिंग गलत हो जाती है । जो यहां हाउस में